

प्रेषक,

मनीषा पंवार,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक, उद्योग,  
उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड,  
पटेल नगर, देहरादून।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग

देहरादून : दिनांक: ०७ दिसम्बर, 2016

विषय:- नाबार्ड की आर0आई0डी0एफ0 योजना के अधीन ग्रामीण हाट काशीपुर, जनपद-उधमसिंहनगर के आंगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक:-88/उ0नि0(पांच)/नाबार्ड- आर0आई0डी0एफ0/2015-16 दिनांक 07.04.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नाबार्ड की आर0आई0डी0एफ0 योजना के अंतर्गत काशीपुर, जनपद-उधमसिंहनगर में ग्रामीण हाट के निर्माण कार्य संबंधी उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 द्वारा तैयार किये गये एवं टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षित आंगणन धनराशि ₹1277.31 लाख के व्यय-वित्त समिति द्वारा अनुमोदित धनराशि ₹1266.93 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2016-17 के अंतर्गत अनुदान संख्या-23 के अधीन "नाबार्ड की आर0आई0डी0एफ0 योजना के अधीन ग्रामीण हाट का निर्माण" योजना में कुल प्राविधानित धनराशि ₹1000.00 लाख में से धनराशि ₹380.00 लाख (रतीन करोड़ अस्सी लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन आपके निर्वर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं:-

- (i) चूंकि D.P.R./Estimate का गठन D.S.R. के अनुसार की गई है, अतः C.P.W.D. Manual के अनुसार कन्टीनजेंसी 4 प्रतिशत के स्थान पर 3 प्रतिशत अनुमन्य होगा।
- (ii) निविदा कार्य में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- (iii) कार्य निर्धारित अवधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय। इस आंगणन के पश्चात् कोई भी आंगणन पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा।
- (iv) वर्तमान परिदृश्य में Energy efficient buildings का निर्माण अत्यन्त महत्वपूर्ण है। अतः भवनों को विश्व स्तर के मानकों के अनुसार Energy Effieient बनाये जाने तथा इस हेतु Builidngs के संबंध में विश्व स्तर के मानकों के अनुरूप व्यवस्था की जाय तथा इस संबंध में Tata Energy Research Institute (TERI) द्वारा जारी Guide line/ Representative designs of energy का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
- (v) सौर ऊर्जा (Solar Energy) के उपयोग का समुचित प्राविधान किया जाय, यथा-सोलर, गीजर, सोलर कुकर आदि।

- (vi) Rain Water harvesting का समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जाय।
- (vii) निर्माण सामग्री यथा Bricks, cement, steel एवं अन्य का Frequency के अनुरूप N.A.B.L. Laboratory से परीक्षण करा लिया जाय।
- (viii) कार्यदायी संस्था कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व कार्य का Structural Design सक्षम स्तर से Vet कराकर एक प्रति राज्य योजना आयोग को भी अवश्य करायेंगे। साथ ही Reinforcement Steel की मात्रा Bar bending Schedule के आधार पर आंकलित किया जाय तथा बचत के संबंध में प्रशासनिक विभाग तथा राज्य-योजना आयोग को अवगत कराया जायेगा।
- (ix) Electical Items जैसे Switches, wires, MCB, MCCB, AC आदि, Plumbing Items जैसे Bath fittings, geyser, water tank, pipes आदि, Toilet items, wood Items आदि की Market Survey कर डी0एस0आर0 दर के अनुरूप गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए प्रशासकीय विभाग के साथ समन्वय कर पूर्व में ही कम से कम 3 निर्माता या उनमें Authorised Distributor के Quotations प्राप्त कर Brand name निर्धारित कर लिया जाय। यदि प्रोक्योरमेंट मर्चें की लागत ₹3.00 लाख से अधिक हो तो कार्यवाही अधिप्राप्ति नियमावली-2008 (यथासंशोधित 2015) के अनुसार की जाय।
- (x) आंगणन में कार्यदायी संस्था द्वारा डी0एस0आर0 की दरें ली गई हैं एवं उसी के अनुरूप मर्चें एवं विशिष्टियां भी उल्लिखित हैं। अतः मितव्ययता के दृष्टिकोण से यह अपहरिहार्य है कि कार्यदायी संस्था योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते समय उन्हीं मर्चों का आंगणन में समायोजन करेंगे जो अपहरिहार्य मर्चें हैं। यह सही है कि यह मद डी0एस0आर0 में हैं, लेकिन स्थल की आवश्यकता को देखते हुए ऐसा यह अपरिहार्य नहीं है कि उनका प्रयोग भी आवश्यक होगा। अतः तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करते समय तकनीकी स्वीकृतकर्ता अधिकारी तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने से पूर्व उन मर्चों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाय।
- (xi) आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का मासिक व्यय विवरण बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड में निर्धारित प्रपत्रों एवं निर्देशों के अनुसार व्यवस्थित करते हुए नियमित रूप से शासन को प्रेषित किया जायेगा।
- (xii) व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। इस संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों/अन्य आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। व्यय मात्र उन्हीं मर्चों में किया जायेगा, जिन मर्चों में धनराशि स्वीकृत की जा रही हैं। यह आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने में बजट मैनुअल/वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों का उल्लंघन होता हो। धनराशि व्यय के उपरांत व्यय की गई धनराशि का मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रपत्र पर नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
- (xiii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश संख्या:-847 /XXVII(1)/2016 दिनांक 26.07.2016 में इंगित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन किया जायेगा।

(xiv) स्वीकृत धनराशि का दिनांक 31.03.2017 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा। वर्षान्त तक स्वीकृत धनराशि के विपरीत वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा। व्यय के पश्चात् यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे दिनांक 31.03.2017 तक शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

2 उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-23 के मुख्य लेखा शीर्ष-2851-ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग, 00-आयोजनागत, 102-लघु उद्योग, 31-नाबार्ड की आर0आई0डी0एफ0 योजना के अधीन ग्रामीण हाट का निर्माण की मानक मद, 24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3 ये आदेश वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के अ0शा0 संख्या:-527(A)/XXVII(2)/2016 दिनांक 07 दिसम्बर, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।  
संलग्नक:- अलॉटमेन्ट आई0डी0।

भवदीया,

(मनीषा पंवार)  
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या: 1935(1)/VII-2-16/02-एम0एस0एम0ई0/2015 टी0सी0 1, तददिनांकित।  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओवराय विल्डिंग माजरा, देहरादून।
2. परियोजना प्रबंधक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, श्रीनगर।
3. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
4. निदेशक, वित्त एवं कोषागार सेवायें, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
5. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
6. गार्ड-फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 आर0 राजेश कुमार)  
अपर सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20162017  
Secretary, Small & Medium Scale Industry (S066)

अलोटमेंट आई डी - S1612230077

आवंटन पत्र दिनांक -07-Dec-2016

पटन पत्र संख्या - .  
अनुदान संख्या - 023

HOD Name - Director Industries (2052)

00 -

1: लेखा शीर्षक 2851 - ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग  
102 - लघु उद्योग

31 - नार्बार्ड की आरआईडीआईडी योजना के अधीन ग्रामीण हाट का निर्माण

00 - -

Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
24 - ग्रहण निर्माण कार्य	8333000	38000000	46333000
	8333000	38000000	46333000

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes -

38000000